

प्रेषक,

डी०एस० गब्र्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 22.12.2015

विषय : नगर पालिका परिषद, नैनीताल के अन्तर्गत ए०बी०सी० कैम्पस निर्माण की स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल के पत्रांक-1464/XV-2(9), दिनांक 04.12.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद, नैनीताल के अन्तर्गत ए०बी०सी० कैम्पस निर्माण (Construction of ABC Campus for Sterilization of stray dogs) की डी०पी०आर० पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य हेतु टी०ए०सी० (वित्त विभाग) द्वारा संस्तुत धनराशि ₹ 42.04 लाख (₹ 39.27 लाख सिविल निर्माण कार्यों हेतु व ₹ 2.77 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त धनराशि ₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ii) निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- (iii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- (v) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (vi) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (vii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।

.2/-....

- (viii) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- (ix) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी
- (x) धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- (xi) वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-400/XXVII(1)/2015, दि०-01.04.2015 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय के अनुदान सं०-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता- 03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास'-20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०- 58/XXVII(2)/2014, दिनांक 17 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई डी-S.150.6/1.30.1.3.7..... के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०एस० गर्ब्याल)

सचिव।

सं०-669 (1)/IV(2)-शा०वि०-2015-105(सा०)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)

संयुक्त सचिव।